



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1947 (श10)
(सं० पटना 1263) पटना, मंगलवार, 22 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
22 जुलाई 2025

सं० वि०सं०वि०-11/2025-3105/वि०सं०—“बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-22 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव ।

[वि०स०वि०-09/2025]

बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025

बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 15, 2011) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहतरवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नांलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की प्रस्तावना में संशोधन।-अधिनियम की प्रस्तावना में, “बिहार राज्य में जल” शब्दों के पश्चात् तथा “या अन्य सामग्री” शब्दों के मध्य से “गैस” शब्द को विलोपित किया जायेगा।

3. बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की धारा-03 की उप-धारा-(1) में संशोधन।-

अधिनियम की धारा-3(1) के प्रथम वाक्य में “जल, गैस या अन्य सामग्री ले जाना” शब्दों के स्थान पर “जल या सामग्री ले जाना” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की धारा-9 की उप-धारा-(2) एवं (3) का प्रतिस्थापन।

- (1) धारा-9(2)-जहाँ किसी भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार राज्य सरकार अथवा निगम में निहित हो गया हो, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम, मुआवजा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, धारा-4 की उप-धारा-1 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तिथि को उस भूमि के बाजार मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत पर परिगणित मुआवजा, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कथित तिथि को भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण सक्षम प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-“बाजार मूल्य” से तात्पर्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर संशोधित बिहार नियमावली में निर्धारित पद्धति के आधार पर निर्धारित मूल्य।

- (2) धारा-9(3)-यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य किसी पक्षकार को स्वीकार्य न हो तो 30 (तीस) दिनों के भीतर व्यथित व्यक्ति भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा परिभाषित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन देगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

5. बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की धारा-10 की उप-धारा-(4) का प्रतिस्थापन।-

धारा-10(4)-यदि मुआवजा अथवा अतिरिक्त मुआवजा या उसके किसी भाग के प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा परिभाषित प्राधिकरण को संदर्भित करेगा और उस पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में जल, गैस या अन्य सामग्री ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषयों के लिए प्रावधान करने के लिए बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 15, 2011) प्रवृत्त है।

उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियमावली गठन के क्रम में यह महसूस किया गया कि नियमावली गठन के पूर्व मूल अधिनियम के कतिपय प्रावधानों में सर्वप्रथम संशोधन आवश्यक है, तदोपरान्त नियमावली का गठन यथोचित होगा। क्योंकि भारत सरकार के स्तर से गठित पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम संख्या, 50) तथा विषयगत अधिनियम में मुआवजा एवं बाजार मूल्य से संबंधित प्रावधानों में अन्तर है। साथ ही, वर्तमान परिपेक्ष्य में किया जाना भी आवश्यक है।

इस विधेयक के अधिनियमित होने के उपरान्त यह अधिनियम सिर्फ जल या अन्य सामग्री को ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषयों के लिए प्रवृत्त होगा। यह अधिनियम गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु भूमि अधिग्रहण पर प्रभावी नहीं होगा। साथ ही, इस संशोधन के प्रभावी होने के उपरान्त मुआवजे की राशि को भी भारत सरकार के समान उस भूमि के बाजार मूल्य के 10% किया जा सकेगा। यदि मुआवजा अथवा बाजार मूल्य अथवा उसके किसी भाग के प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसका निराकरण भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 अन्तर्गत यथा परिभाषित प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

अतः यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।

(संजय सरावगी)

भार-साधक सदस्य

पटना,

दिनांक-22.07.2025

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1263-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>